

भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1241
मंगलवार, 03 दिसम्बर, 2024 (12 अग्रहायण, 1946, (शक)) को उत्तरार्थ

सहकारी समितियों के लिए राष्ट्रीय स्तर का डाटाबेस

1241. श्री प्रदीप कुमार सिंह:

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार सहकारी समितियों के लिए कोई राष्ट्रीय स्तर का डाटाबेस तैयार कर रही है;
- (ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है;
- (ग) उक्त डाटाबेस में शामिल सहकारी समितियों का व्यौरा क्या है; और
- (घ) उक्त डाटाबेस विभिन्न हितधारकों द्वारा उपयोग किए जाने के लिए कब तक तैयार हो जाएगा?

उत्तर
सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)

(क) और (ख) भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय ने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के सहयोग से एक व्यापक राष्ट्रीय सहकारी डाटाबेस (एनसीडी) विकसित किया है। इस उद्देश्य के लिए राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारियों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों की सभी सहकारी समितियों का डाटा डाटाबेस में दर्ज किया गया है।

एनसीडी को चरणबद्ध तरीके से तीन चरणों में विकसित किया गया है। फरवरी 2023 में पूर्ण हुए चरण-। में, जिला रजिस्ट्रार कार्यालयों और एआईसीटीई के 500 स्थानीय प्रशिक्षकों की मदद से कृषि, डेयरी और मास्तिकी में लगभग 2.64 लाख प्राथमिक सहकारी समितियों का मानचित्रण किया गया। चरण-॥ में राष्ट्रीय सहकारी समितियों/महासंघों और राज्य और जिला स्तरों के साथ उनके संबंधों का मानचित्रण करना, विभिन्न सहकारी बैंकों और महासंघों से डेटा एकत्र करना शामिल था। मई 2023 में शुरू किए गए चरण-॥। में, डेटाबेस को अन्य क्षेत्रों में 5.3 लाख से अधिक सहकारी समितियों तक उनके संबंधित RCS कार्यालयों के माध्यम से लगभग सभी राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा डाटा प्रविष्टियां पूर्ण किए जाने तक विस्तारित किया गया।

(ग) एनसीडी पोर्टल के अनुसार, दिनांक 28.11.2024 तक सहकारी समितियों का राज्यवार और क्षेत्रवार विवरण क्रमशः अनुलग्नक-। और अनुलग्नक-॥ में संलग्न है।

(घ) डेटाबेस अब URL: <https://cooperatives.gov.in> पर चालू है।

एनसीडी पोर्टल के अंतर्गत देश भर में सहकारी समितियों का राज्यवार विवरण
(28.11.2024 तक)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	समितियों कि संख्या
1	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2,223
2	आंध्र प्रदेश	17,628
3	अरुणाचल प्रदेश	1,276
4	असम	10,984
5	बिहार	25,580
6	चंडीगढ़	476
7	छत्तीसगढ़	10,612
8	दिल्ली	5,944
9	गोवा	5,492
10	गुजरात	82,829
11	हरियाणा	32,936
12	हिमाचल प्रदेश	5,293
13	जम्मू और कश्मीर	9,883
14	झारखण्ड	11,488
15	कर्नाटक	45,169
16	केरल	7,882
17	लद्दाख	270
18	लक्ष्मीप	42
19	मध्य प्रदेश	53,566
20	महाराष्ट्र	2,22,647
21	मणिपुर	11,439
22	मेघालय	3,053
23	मिजोरम	1,262
24	नागालैंड	8,073
25	ओडिशा	7,566
26	पूर्वुचेरी	461
27	ਪंजाब	19,089
28	राजस्थान	39,305
29	सिक्किम	3,799
30	तमिलनाडु	22,124
31	तेलंगाना	60,397
32	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	550
33	त्रिपुरा	3,142
34	उत्तर प्रदेश	44,606
35	उत्तराखण्ड	5,423
36	पश्चिम बंगाल	31,543
	कुल	8,14,052

एनसीडी पोर्टल के अंतर्गत देश में सहकारी समितियों का क्षेत्रवार विवरण
(28.11.2024 तक)

क्रम सं.	क्षेत्रक	समितियों कि संख्या
1	कृषि एवं संबद्ध सहकारी समिति	27,335
2	कृषि प्रसंस्करण/औद्योगिक सहकारी समिति	23,218
3	मधुमक्खी पालन सहकारी समिति	337
4	उपभोक्ता सहकारी समिति	22,136
5	क्रेडिट और थ्रिफ्ट समिति	81,157
6	डेयरी सहकारी समिति	1,44,376
7	शिक्षा और प्रशिक्षण सहकारी समिति	499
8	मात्स्यिकी सहकारी समिति	25,671
9	हस्तशिल्प सहकारी समिति	5,186
10	हथकरघा और बुनकर सहकारी समिति	19,646
11	आवास सहकारी समिति	1,93,054
12	जूट और कॉयर सहकारी समिति	64
13	श्रमिक सहकारी समिति	45,230
14	पशुधन एवं कुकुट सहकारी समिति	16,785
15	विपणन सहकारी समिति	9,324
16	विविध ऋण सहकारी समिति	6,066
17	विविध गैर क्रेडिट सहकारी समिति	31,285
18	बहुउद्देशीय सहकारी समिति	20,581
19	प्राथमिक कृषि क्रेडिट समिति (PACS)	1,06,162
20	रेशम उत्पादन सहकारी समिति	500
21	सामाजिक कल्याण एवं सांस्कृतिक सहकारी समिति	2,105
22	चीनी मिल सहकारी समिति	285
23	पर्यटन सहकारी समिति	485
24	परिवहन सहकारी समिति	4,181
25	जनजातीय- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सहकारी समिति	1,566
26	शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी)	1,423
27	महिला कल्याण सहकारी समिति	25,395
	कुल	8,14,052